



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26052026-272870  
CG-MH-E-26052026-272870

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ ज्येष्ठ 5, 1948

No. 343]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/ JYAISTHA 5, 1948

यूनियन बैंक ऑफ इंडियन

अधिसूचना

मुंबई, 26 मई, 2026

**फा.सं. सीओ:ईआरडी:पीडी:225:2026.-** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 4/2/1/2022-IR, दिनांक 13 मार्च, 2024 के अनुसरण में की गयी या करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर, 1 नवम्बर, 2022 से इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमन, 2026 कहा जाएगा.  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 (जिसे आगे उक्त विनियमन कहा जाएगा) में, विनियम 3 के खंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(एफ) चिकित्सा सुविधाओं तथा अवकाश किराया रियायत के प्रयोजनों हेतु किसी अधिकारी कर्मचारी के संबंध में ‘परिवार’, से तात्पर्य-

- (i) अधिकारी कर्मचारी के पति या पत्नी,
- (ii) पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित)
- (iii) पूर्णतः आश्रित शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग भाई या बहन जो चालीस प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हों;
- (iv) विधवा पुत्रियां और आश्रित तलाकशुदा/पति से अलग हुई पुत्रियां;
- (v) बहनें, जिसमें अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्त या पति से अलग रह रही अथवा विधवा बहनें सम्मिलित हैं; तथा
- (vi) अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता, से है:

बशर्ते कि शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में, आयु की परवाह किए बिना, उन्हें विवाह के पश्चात भी आश्रित माना जाएगा, बशर्ते कि वे आश्रित होने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।

**स्पष्टीकरण 1-** "पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्य" से अभिप्राय परिवार के ऐसे सदस्य से है जिसकी मासिक आय ₹18,000/- से अधिक न हो तथा यदि माता-पिता में से किसी एक की मासिक आय ₹18,000/-से अधिक है अथवा माता-पिता दोनों की कुल मासिक आय ₹18,000/- से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।

**स्पष्टीकरण 2.-** चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना तथा अवकाश किराया रियायत के प्रयोजनों हेतु, सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए आश्रित पिता, माता, ससुर एवं सास में से किसी दो को कवर किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी के पास एक कैलेंडर वर्ष में एक बार इन आश्रितों में से किसी एक अथवा दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

**स्पष्टीकरण 3.-** यह परिभाषा दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी तथा कैलेंडर वर्ष 2024 हेतु, चिकित्सा बीमा योजना या पॉलिसी के प्रयोजन हेतु, आश्रितों के संशोधित मासिक आय मानदंड दिनांक 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

3. उक्त विनियमन के विनियम 4 में, -

(ए) उप-विनियम (7) में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(बी) उप-विनियम (9) और (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(9) 1 नवंबर, 2022 से प्रत्येक वर्ग के समक्ष निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

(ए) शीर्ष कार्यपालक वर्ग

वेतनमान VIII = ₹ 253000 – 9000/4 – 289000

वेतनमान VII = ₹ 156500 - 4340/4 – 173860

वेतनमान VI = ₹ 140500 – 4000/4 - 156500

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग

वेतनमान V = ₹ 120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 - 135020

वेतनमान IV = ₹ 102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(सी) मध्य प्रबंधन वर्ग

वेतनमान III = ₹ 85920 -2680/5- 99320 - 2980/2 - 105280

वेतनमान II = ₹ 64820 – 2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन वर्ग

वेतनमान I = ₹ 48480 -2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

**स्पष्टीकरण - प्रत्येक अधिकारी जो** 31 अक्टूबर, 2022 को लागू वेतनमान के अधीन है, उसे 1 नवंबर, 2022 से इस उप-विनियमन में निर्धारित वेतनमान में चरण-दर-चरण आधार पर फिट किया जाएगा, अर्थात्, संबंधित वेतनमान में पहले चरण से आगे के समकक्ष चरणों में और वेतन वृद्धि सामान्य रूप से वार्षिकी तिथि होगी, बशर्ते जहां अन्यथा प्रावधान किया गया हो.

(10) उप-विनियम (1) से (9) में निहित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को प्रत्येक समय इन सभी वर्गों में सेवारत अधिकारी रखने की आवश्यकता है.

(11) 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को देय विशेष भत्ते निम्नानुसार होंगे:

वेतनमान I-III – मूल वेतन का 7.75 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV- V – मूल वेतन का 10 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI-VII – मूल वेतन का 11 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

(12) 1 नवंबर, 2017 से अधिकारियों को देय विशेष भत्ते निम्नानुसार होंगे:

वेतनमान I-III – मूल वेतन का 16.40 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV- V – मूल वेतन का 19 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI-VIII – मूल वेतन का 20 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

बशर्ते कि वेतनमान VIII का अधिकारी 31 मार्च, 2020 से विशेष भत्ते के लिए पात्र होगा.

(13) नवंबर, 2022 से अधिकारियों को देय विशेष भत्ते निम्नानुसार होंगे:

वेतनमान I - मूल वेतन का 26.50 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान II-III - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV-V - मूल वेतन का 30.50 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI-VII - मूल वेतन का 31.50 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VIII - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

**नोट:** उप-विनियम (11), (12) एवं (13) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते तथा उस पर लागू महंगाई भत्ते की गणना सेवानिवृत्ति लाभों जैसे पेंशन, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना), सहित भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में नहीं की जाएगी.

4. उक्त विनियमन के विनियम 5 में, -

(ए) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(1) विनियमन 4 के उप-विनियम (9) के प्रावधानों के अधीन, 1 नवंबर, 2022 से वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात: -

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (9) में निर्धारित वेतनमान में निर्दिष्ट वेतन-वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, वार्षिक आधार पर उपार्जित होगी और वे जिस माह में देय होंगी, उस माह के पहले दिन प्रदान की जाएगी ;

(बी) संबंधित वेतनमानों में अधिकतम स्तर तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अगले उच्चतर वेतनमान में ठहराव वेतन-वृद्धि के साथ वेतन-वृद्धि प्रदान की जाएगी, जैसा कि नीचे खंड (ग) में निर्दिष्ट है, बशर्ते कि वे दक्षता मानदंड को पार कर लें;

(सी) कनिष्ठ प्रबंधन वर्ग वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद खंड (बी) के अनुसार मध्यम प्रबंधन वर्ग वेतनमान II के वेतनमान में चले गए हैं, प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर सात ठहराव वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो वेतन-वृद्धियां 2680/- रुपये प्रत्येक और अगली पाँच वेतन-वृद्धियां 2980/- रुपये प्रत्येक होंगी:

बशर्ते कि अधिकारी पाँचवी ठहराव वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2022 को, जो भी बाद में हो, छठी ठहराव वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होगा ;

यह भी प्रावधान है कि अधिकारी पाँचवी ठहराव वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2022 को, जो भी बाद में हो, सातवीं ठहराव वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होगा ;

(डी) मध्य प्रबंधन वर्ग वेतनमान II के वे अधिकारी, जो खंड (बी) के अनुसार उच्चतर वेतनमान की अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन वर्ग के वेतनमान III में चले गए हैं , प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर 2980/- रुपए प्रत्येक, सात ठहराव वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी पाँचवी ठहराव वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2022 को, जो भी बाद में हो, छठी ठहराव वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

यह भी प्रावधान है कि अधिकारी पाँचवी ठहराव वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2022 को, जो भी बाद में हो, सातवीं ठहराव वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

(ई) मध्य प्रबंधन वर्ग वेतनमान III में नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी अर्थात, वे अधिकारी जो मध्य प्रबंधन वर्ग वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत किए गए हैं, वेतनमान के अधिकतम वेतन स्तर पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर आठ ठहराव वेतन वृद्धियों के पात्र होंगे, जिनमें प्रथम चार ठहराव वेतनवृद्धियां 2980/-रुपये प्रत्येक तथा अगली चार ठहराव वेतनवृद्धियां 3360/- रुपये प्रत्येक होंगी:

बशर्ते कि छठी ठहराव वेतन वृद्धि के जारी होने के दो वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022 जो भी बाद में हो, सातवीं ठहराव वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

यह भी प्रावधान है कि छठी ठहराव वेतन वृद्धि के जारी होने के चार वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022 जो भी बाद में हो, आठवीं ठहराव वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

(एफ) वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम वेतन स्तर पर पहुंचने के पश्चात, प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर पाँच ठहराव वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली ठहराव वेतन-वृद्धि 3360/- रुपये की होगी और अगली चार ठहराव वेतन वृद्धि 3680/- रुपये प्रत्येक होगी:

बशर्ते कि अधिकारी द्वितीय ठहराव वेतन-वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात अथवा 1 नवम्बर, 2022 को, जो भी बाद में हो, तृतीय ठहराव वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

यह भी प्रावधान है कि अधिकारी द्वितीय ठहराव वेतन-वृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात अथवा 1 नवम्बर, 2022 को, जो भी बाद में हो, चतुर्थ ठहराव वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

यह भी प्रावधान है कि अधिकारी द्वितीय ठहराव वेतन-वृद्धि जारी होने के छह वर्ष पश्चात अथवा 1 नवम्बर, 2022 को, जो भी बाद में हो, पाँचवीं ठहराव वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

(जी) वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग वेतनमान V के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम वेतन स्तर पर पहुंचने के पश्चात, प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर 4000/- रुपये प्रत्येक की चार ठहराव वेतन वृद्धियों के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के चार वर्ष पश्चात अथवा 1 नवम्बर, 2022 को, जो भी बाद में हो, द्वितीय ठहराव वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

यह भी प्रावधान है कि अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के छह वर्ष पश्चात अथवा 1 नवम्बर, 2022 को, जो भी बाद में हो, तृतीय ठहराव वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

यह भी प्रावधान है कि अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के आठ वर्ष पश्चात अथवा 1 नवम्बर, 2022 को, जो भी बाद में हो, चतुर्थ ठहराव वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

(एच) शीर्ष प्रबंधन वर्ग वेतनमान VI के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात, प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर तीन ठहराव वेतन वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, जिनमें प्रथम दो ठहराव वेतन वृद्धियां 4000/- रुपये की प्रत्येक तथा तृतीय ठहराव वेतनवृद्धि 4340/- रुपये की होगी:

बशर्ते कि वे अधिकारी जो पहले से ही वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंच गए हैं, 4000/- रुपये की प्रथम ठहराव वेतन वृद्धि के लिए वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष के पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, पात्र होंगे:

यह भी प्रावधान है कि वे अधिकारी जो पहले से ही वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंच गए हैं, 4000/-

रुपये की द्वितीय ठहराव वेतन वृद्धि के लिए वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के चार वर्षों के पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, पात्र होंगे:

यह भी प्रावधान किया गया है कि वे अधिकारी जो पहले से ही वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंच गए हैं, 4340/- रुपये की तृतीय ठहराव वेतन वृद्धि के लिए वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के छह वर्षों के पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, पात्र होंगे:

(आई) शीर्ष प्रबंधन वर्ग वेतनमान VIII के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात, प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर 4340/- रुपये की प्रत्येक तीन ठहराव वेतन वृद्धियों के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि वे अधिकारी जो पहले से ही वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंच गए हैं, प्रथम ठहराव वेतन वृद्धि के लिए, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष के पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, पात्र होंगे:

यह भी प्रावधान है कि वे अधिकारी जो पहले से ही वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंच गए हैं, द्वितीय ठहराव वेतन वृद्धि के लिए, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के चार वर्षों के पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, पात्र होंगे:

यह भी प्रावधान किया गया है कि वे अधिकारी जो पहले से ही वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंच गए हैं, तृतीय ठहराव वेतन वृद्धि के लिए वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के छह वर्षों के पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, पात्र होंगे:

**नोट:** इस उप-विनियम के खंड (ए) से (आई) में उल्लिखित वेतनवृद्धियां ऐसे अधिकारी को प्रदान नहीं की जाएंगी, जो पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है।

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतन वृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके मूल पद के अनुसार यथावत बने रहेंगे."

(बी) उप-विनियम (2) में-

(i) स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उपबंध जोड़े जाएंगे अर्थात:-

“बशर्ते कि 1 नवंबर, 2022 से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी-II) भाग II परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी उनके वेतनमान में दो वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट परीक्षा या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी-I) भाग I परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे:

यह भी प्रावधान है कि जो अधिकारी 1 नवंबर, 2022 को बैंक की सेवा में थे तथा जिन्होंने पहले ही सीएआईआईबी-II उत्तीर्ण कर लिया है, वे 1 नवंबर, 2022 से अथवा सीएआईआईबी-II उत्तीर्ण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, द्वितीय अतिरिक्त वेतन वृद्धि हेतु पात्र होंगे:

यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में, जहां कोई अधिकारी 8 मार्च, 2024 को या उससे पहले वेतनमान की उच्चतर या अधिकतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात जेएआईआईबी या सीएआईआईबी-I या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) उत्तीर्ण करता है (जेएआईआईबी या सीएआईआईबी के मामले में) या वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने से एक चरण पहले उत्तीर्ण करता है/किया है (जेएआईआईबी या सीएआईआईबी-I या सीएआईआईबी-II के मामले में), और ऐसी योग्यता प्राप्त करने पर अन्यथा देय वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं किया है जहां ऐसे कर्मचारी जिनके वेतनमान में वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की जा सकती, ऐसे मामले में उन कर्मचारियों के ठहराव वेतन वृद्धि को एक या दो वर्ष पहले की जा सकती है, जैसा भी मामला हो."

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (एच) के पश्चात् और नोट से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(i) 1 नवंबर, 2022 से, अन्य बातों के समान रहने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा नीचे दी गई तालिका के अनुसार संशोधित होगी, अर्थात: -

#### तालिका

जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भाग I परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात ₹1370/- प्रति माह
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिया हो	(ए) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद ₹1370/- प्रति माह. (बी) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष बाद ₹3425/- प्रति माह; (सी) वेतनमान के (अधिकतम स्तर पर पहुंचने के तीन वर्ष पश्चात ₹5480/- प्रति माह

बशर्ते कि वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी को ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्त, ऐसी व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त के जारी होने की तारीख के आधार पर जारी होगी;

यह भी प्रावधान है कि ,1 नवंबर ,2022 से वेतनमान ,VIII में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को व्यावसायिक योग्यता भत्ता देय नहीं होगा.

नोट में, खंड (V) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“(vi) वे अधिकारी जो दिनांक 1 नवंबर, 2022 को बैंक की सेवा में थे तथा जिन्होंने पहले ही जेएआईआईबी या सीएआईआईबी या सीएआईआईबी II उत्तीर्ण कर लिया है और जिन्हें व्यावसायिक योग्यता वेतन- II प्राप्त कर रहे हैं, वे व्यावसायिक योग्यता वेतन-III के लिए पात्र होंगे, जो कि व्यावसायिक योग्यता वेतन-II के जारी होने के एक वर्ष पश्चात् या 1 नवंबर, 2022 से, जो भी बाद में हो देय होगा.

(vii) वे अधिकारी जिन्होंने जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) उत्तीर्ण कर लिया है तथा 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुके हैं. और जिन्हें 1 नवंबर, 2022 तक प्रथम ठहराव वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वे नवंबर, 2022 से व्यावसायिक योग्यता वेतन-I के लिए पात्र होंगे तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्ते इस खंड के अंतर्गत व्यावसायिक योग्यता वेतन-I के जारी होने की तारीख के आधार पर जारी किया जाएगा.

(सी) उप-विनियम (3) में, -

(i) खंड (जी) में, तालिका के पश्चात्, नोट (i) से (vi) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (एच) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(i) 1 नवंबर, 2022 से, अन्य बातें समान रहने पर, मकान किराया भत्ता के साथ निश्चित व्यक्तिगत वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए यथावत रहेंगे:-

#### तालिका

वेतन वृद्धि घटक (रु.)	1 नवंबर, 2022 को वेतन वृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता(रु)	बैंक आवास उपलब्ध होने की स्थिति में देय कुल निश्चित व्यक्तिगत वेतन (रु.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669

नोट:

(i) इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) एवं आई में निर्दिष्ट तालिका के कॉलम (3) के अंतर्गत दर्शाये गए निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक आवास उपलब्ध कराया गया है.

(ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन, खंड (आई) के अंतर्गत उक्त तालिका के कॉलम (1) और (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल राशि का योग तथा संबंधित अधिकारी द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), एवं (9) में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि अर्जित करने पर प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता होगा.

- (iii) केवल वे अधिकारी जो 1 नवम्बर, 1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में थे, वे अपने अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष बाद निश्चित वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे, जिसमें उन्हें रखा गया है।
- (iv) 1 नवम्बर, 1999 को या से, निश्चित वैयक्तिक वेतन जारी किए जाने के कारण उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण के खंड (सी) में वर्णित व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी किए जाने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- वर्तमान जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पूर्ववर्ती उपबंधों के कारण एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाई गई है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके पश्चात जारी होने वाली है, वह अधिकारी को इसी तारीख को या से जारी की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।
- (v) निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन का वेतन वृद्धि घटक की गणना अधिवर्षिता लाभ के लिए की जाएगी।
- (vi) कोई अधिकारी, जिसने उपर्युक्त खंड (ए) के अनुसार वेतन वृद्धि पहले अर्जित की है, वह इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच), एवं (आई) में उल्लिखित निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन की मात्रा, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात प्राप्त करेगा।”

#### 5. उक्त विनियमन के विनियम 21 में:-

(ए) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण के अंतर्गत, खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(बी) व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन जैसा कि विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण के खंड (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) तथा (आई) में निर्दिष्ट है, महंगाई भत्ते के लिए गणनीय होगा”

(बी) उप-विनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(8) दिनांक 1 नवम्बर, 2022 से,-

(ए) महंगाई भत्ता वेतन के प्रति प्रतिशत बिंदु सूचकांक पर 1 प्रतिशत की दर से देय होगा।

(बी) उपर्युक्त प्रकार से महंगाई भत्ता, औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधार 2016=100. के तिमाही औसत में 123.03 अंको से प्रत्येक वृद्धि या कमी पर देय होगा; तथा सीपीआई 2016 में 123.03 अंको से ऊपर प्रत्येक दशमलव के दहाई अंक के परिवर्तन पर वेतन पर 0.01 प्रतिशत महंगाई भत्ते में परिवर्तन किया जाएगा

(सी) महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन नियमानुसार त्रैमासिक आधार पर 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर, 1 फरवरी को निम्नानुसार जारी किया जाएगा, अर्थात:-

महंगाई भत्ता जारी होने की तिथि	महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अंकों का तिमाही औसत	प्रयोज्य माह
1 मई	जनवरी, फ़रवरी और मार्च	मई, जून और जुलाई
1 अगस्त	अप्रैल, मई और जून	अगस्त, सितंबर और अक्टूबर
1 नवंबर	जुलाई, अगस्त और सितंबर	नवंबर, दिसंबर और जनवरी
1 फरवरी	अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर	फरवरी, मार्च और अप्रैल;

(डी) महंगाई भत्ते पर कोई सीमा नहीं होगी;

(ई) तिमाही औसत की गणना करते समय, केवल पहले दो दशमलव स्थानों को ही ध्यान में रखा जाएगा.

6. उक्त विनियमन के विनियम 22 में उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) 1 नवंबर, 2022 को और से,-

(क) जहाँ बैंक द्वारा किसी अधिकारी को आवास सुविधा प्रदान की जाती है, वहाँ उससे उसके वेतनमान के प्रथम चरण में उसके मूल वेतन का 0.35 प्रतिशत अथवा उस आवास का मानक किराया, जो भी कम हो, की राशि वसूल की जाएगी;

(ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवास सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, तो वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा, अर्थात्-

तालिका

क्रमांक	कार्य का स्थान	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)	(3)
1.	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर और समूह 'ए' में शामिल परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 10.0%
2.	क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह बी तथा गोवा राज्य में स्थित परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 9.0%
3.	अन्य स्थान	वेतन का 8.0%:

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता उसके द्वारा आवास सुविधा के लिए भुगतान किए गए वास्तविक किराए और जिस वेतनमान में वह है उस वेतनमान के प्रथम चरण में वेतन के 0.35 प्रतिशत के अंतर के बराबर होगा, और यह उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित मकान किराया भत्ते के अधिकतम 150 प्रतिशत तक होगा.

**नोट:** अधिकारियों द्वारा अपने स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावों को पहले की तरह मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा.”.

7. उक्त विनियमन के विनियम 23 में, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“23. (1) 1 नवंबर, 2022 को और से यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट स्थान पर सेवारत है, तो उस स्थान के लिए कॉलम (3) में निर्दिष्ट दर पर एक शहर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा:

तालिका		
क्रम संख्या	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्र 1 और उससे उच्चतर और गोवा राज्य में स्थित स्थान	2300/- रुपये प्रति माह
2.	पांच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान, राज्य की राजधानियाँ और चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर	1900/- रुपये प्रति माह.

(2) 1 नवंबर, 2022 को और से विशेष क्षेत्र भत्तों की दरें, इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी:

बशर्ते कि यदि अनुसूची के कॉलम (1) में दर्शाए गए किसी भी स्थान पर, उप-विनियमन (10) के अंतर्गत प्रदत्त पर्वतीय एवं ईंधन भत्ता भी देय हो, तो ऐसे में अधिकारी केवल दोनों भत्तों में से उच्चतर भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा, दोनों भत्ते एक साथ नहीं.:

इसके अतिरिक्त, यदि दोनों भत्तों में से जो भी अधिक भत्तों की राशि हो, वह 31 दिसंबर, 1989 को अधिकारी द्वारा प्राप्त विशेष भत्ता और पर्वतीय एवं ईंधन भत्ते के कुल योग से कम हो, तो यह अंतर व्यक्तिगत भत्ते के रूप में तब तक संरक्षित रहेगा जब तक अधिकारी उस स्थान पर रहता है.

(3) 1 नवंबर, 2017 को और से, यदि कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी में आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत है, तो वह क्षेत्र के समूह ए या समूह बी के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः 600/- रुपये प्रति माह या 525/- रुपये प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए पात्र होगा.

(4) 1 अप्रैल, 2024 को और से, यदि किसी अधिकारी का तबादला किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है और यदि उसके पूर्व स्थान पर एक या अधिक बच्चे विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ रहे हों, तो वह बाद वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर शैक्षणिक वर्ष के अंत तक, अधिकतम दो बच्चों हेतु, प्रति बच्चा 2500/- रुपये प्रति माह के मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते का पात्र होगा,.

बशर्ते कि यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ना बंद कर दें तो ऐसा भत्ता देय नहीं रहेगा.

(5) 1 अप्रैल 2024 को और से, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़े वेतनमान प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है, जो अधिकतम 7500/- रुपये प्रति माह तक होगा, और ऐसे अन्य भत्ते भी प्राप्त कर सकता है जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर प्राप्त होते.

बशर्ते कि यदि ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है या किसी ऐसे प्रशिक्षण संस्थान में जो बैंक के स्वामित्व में नहीं है, जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले तैनात था, तो उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा, जो अधिकतम 3750/- रुपये प्रति माह तक होगा.

बशर्ते यह भी कि जहाँ किसी अधिकारी को उसी नगरपालिका सीमा या शहरी समूह के भीतर स्थित किसी अन्य कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है, और मेट्रो या प्रमुख 'A' श्रेणी के शहरों में ऐसी प्रतिनियुक्ति की दूरी उसके मूल (पैरेंट) शाखा या कार्यालय से बीस किलोमीटर या उससे अधिक है, तो वह अधिकारी नियम 41 के उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अस्थायी निवास भत्ता (हॉलिंग अलाउंस) प्राप्त करने का पात्र होगा.

- (6) 1 अप्रैल, 2024 को और से, यदि किसी अधिकारी को उच्च वेतनमान के किसी पद पर लगातार कम से कम चार दिनों तक या किसी कैलेंडर माह में कुल चार दिनों तक कार्यवाहक के रूप में कार्य करना आवश्यक हो, तो उसे कार्यवाहक अवधि के लिए आनुपातिक रूप से उसके मूल वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर कार्यवाहक भत्ता प्राप्त होगा और कार्यवाहक भत्ता केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में गिना जाएगा.

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अंतर्गत पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप ही उच्च वेतनमान में कार्यवाहक के रूप में नियुक्त होता है, तो वह वर्गीकरण की समीक्षा के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यवाहक भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा.

- (7) 1 अप्रैल, 2024 को और से, एक अधिकारी प्रत्येक समापन के लिए 1500/- रुपये प्रति तिमाही के समापन भत्ते का पात्र होगा.
- (8) 1 नवंबर, 2017 को और से, यदि एक दिन के कार्य घंटों को कम से कम दो घंटे के अंतराल पर विभाजित किया जाता है, तो अधिकारी प्रति कार्य घंटे 300 रुपये प्रति माह की दर से विभाजित कार्य भत्ता का पात्र होगा.
- (9) यदि किसी अधिकारी को छुट्टी के दिन तिजोरी या लॉकर के संरक्षक के रूप में काम करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उस दर पर दैनिक भत्ता देय होगा जिस दर पर वह पात्र है.
- (10) 1 नवंबर 2022 को और से, एक अधिकारी पर्वतीय और ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	स्थान (1)	दर (2)
(1)	(2)	(3)
1.	1000 मीटर या उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मरकारा शहर	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 1450 रुपये प्रति माह तक.
2.	1500 मीटर या उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 1900 रुपये प्रति माह तक.
3.	3000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5 प्रतिशत, अधिकतम 3750 रुपये प्रति माह तक.

- (11) 1 नवंबर 2022 को और से, एक अधिकारी 850 रुपये प्रति माह के जानार्जन भत्ते के साथ-साथ महंगाई भत्ता पाने का पात्र होगा.

नोट: लागू महंगाई भत्ता सहित शिक्षण भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभों, अर्थात् पेंशन जिसमें परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) भी शामिल है, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा.

- (12) 1 नवंबर, 2022 को और से, एक अधिकारी 1200/- रुपये प्रति माह के निश्चित स्थान भत्ते के लिए पात्र होगा, जो उन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में तैनात है जो शहर क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए पात्र हैं, जिसे महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ, अर्थात् पेंशन जिसमें परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) शामिल है, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नहीं गिना जाएगा।
- (13) (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से निम्नलिखित चयनित मापदंडों में से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार, बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर, कार्यनिष्पादन-आधारित प्रोत्साहन सभी अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा अर्थात्: -
- चालू खाता बचत खाता;
  - गैर-निष्पादित आस्तियां;
  - विशेष उल्लेख खाते;
  - गैर-ब्याज आय;
  - कुल कारोबार;
  - लाभप्रदता;
  - आस्तियों पर प्रतिफल या इक्विटी पर प्रतिफल;
  - सरकारी योजनाएँ।
- (ख) कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा खंड (क) में उल्लिखित मापदंडों के आधार पर 0-15 (अधिकतम) दिनों के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) में देय होगी।

8. उक्त विनियमन के विनियम 24 में, -

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“1 नवंबर, 2022 को और से प्रभावी रूप से, कोई अधिकारी स्वयं एवं अपने परिवार के लिए चिकित्सीय व्ययों के प्रतिपूर्ति का पात्र होगा, बशर्ते कि अधिकारी द्वारा ऐसे व्यय किए जाने का स्वप्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए तथा दावा की गई राशि के लिए लेखा विवरण संलग्न किया गया हो, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्-

तालिका

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	अवर प्रबंधन और मध्य प्रबंधन ग्रेड	13000/- रुपये प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, इनमें से जो भी कम हो।
2.	वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक ग्रेड	15400/- रुपये प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, इनमें से जो भी कम हो।

**नोट 1 :** किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है जो की किसी भी समय ऊपर दी गई अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक न हो।

**नोट 2:** कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में दो महीनों, अर्थात् नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के लिए अनुपातिक रूप से वृद्धि की जाएगी.

(ख) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित जाए, अर्थात्:-

“(4) सभी अधिकारी नेत्र जांच के लिए प्रति वर्ष 500 रुपये की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे.

9. उक्त विनियमन के विनियम 25 में, उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, 1 नवंबर, 2022 को और से, बैंक किसी अधिकारी को उसके वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर या आवास के मानक किराए, जो भी कम हो, के भुगतान पर आवास सुविधा प्रदान कर सकता है:

बशर्ते कि यदि अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, तो बैंक द्वारा उससे वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.075 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी:

इसके अतिरिक्त, यदि बैंक द्वारा ऐसी आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो बिजली, पानी, गैस और साफ-सफाई के शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे.”.

10. उक्त विनियमन के विनियम 31 में निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किया जाएगा. अर्थात्:-

बशर्ते कि, यदि स्वीकृति प्राधिकारी अधिकारी की छुट्टी अस्वीकार करता है या स्थगित करता है, तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा.

11. उक्त विनियमन के विनियम 32 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) 1 अप्रैल, 2024 को और से, एक अधिकारी कर्मचारी वर्ष में दो दिन की आकस्मिक छुट्टी को चार बार आधे दिन की छुट्टी के रूप में लाभ उठाने हेतु पात्र होगा, जिनमें से दो अवसर सुबह के और दो अवसर दोपहर के होंगे.

बशर्ते कि इस श्रेणी के अंतर्गत आकस्मिक अवकाश लेने के लिए चौबीस घंटे पहले आवेदन करना आवश्यक होगा:

इसके अतिरिक्त, आकस्मिक अवकाश की शेष राशि को अनुपयोगित आकस्मिक अवकाश खाते में स्थानांतरित करते समय, शेष राशि में यदि कोई अंश हो तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा.

12. उक्त विनियमन के विनियम 33 में, -

(ए) उप-विनियम (4) और (5) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(4) 1 जून, 2015 को या से विशेषाधिकार अवकाश अधिकतम दो सौ सत्तर दिनों तक संचित किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को या से, विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ पचपन दिनों तक सीमित रहेगा:

इसके अतिरिक्त, एक अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्योहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में पांच दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश भुनाने हेतु भी पात्र होगा और जो अधिकारी पचपन वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर चुके हैं, वे अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सात दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश भुनाने के पात्र होंगे.

(5) विशेषाधिकार अवकाश का लाभ लेने के इच्छुक अधिकारी को अवकाश किराया रियायत के उद्देश्य को छोड़कर, ऐसे अवकाश का लाभ लेने के अपने उद्देश्य की सूचना सामान्यतः दस दिन पहले देनी होगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को या उससे पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने हेतु दस दिन की अग्रिम सूचना की आवश्यकता नहीं होगी.

(बी) उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को शामिल किया जाएगा\_अर्थात्:-

“(7) 1 अप्रैल, 2024 को और से विशेषाधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजनों के लिए, आकस्मिक अवकाश और अनिवार्य अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाशों को बाहर रखा जाएगा.”

13. उक्त विनियमन के विनियम 34 में,-

(ए) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे. अर्थात्:-

बशर्ते कि, 1 अप्रैल, 2024 को और से, एक अधिकारी प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक महीने की दर से अस्वस्थता अवकाश का हकदार होगा:

इसके अतिरिक्त, अधिकारी की संपूर्ण सेवा अवधि में कुल बीमार अवकाश (नियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त बीमार अवकाश सहित) सात सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगा.

(बी) उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे. अर्थात्:-

“(6) 1 अप्रैल, 2024 को और से, एकल पुरुष अभिभावक कर्मचारी अपने आठ वर्ष और उससे कम आयु के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन बीमारी अवकाश का लाभ उठा सकता है.

(7) 1 अप्रैल, 2024 को और से महिला कर्मचारी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए प्रति माह एक दिन का अस्वस्थता अवकाश ले सकती है.

- (8) 1 अप्रैल, 2024 को और से, अधिकारी कर्मचारी अपने पंद्रह वर्ष या उससे कम आयु के विशेष बच्चे की अस्वस्थता के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिनों का अस्वस्थता अवकाश ले सकते हैं, बशर्ते वे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.
- (9) 1 अप्रैल, 2024 को और से, 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिकारी कर्मचारी कार्यस्थल के अतिरिक्त किसी अन्य केंद्र में अपने जीवनसाथी के अस्पताल में भर्ती होने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीस दिनों की अस्वस्थता अवकाश ले सकते हैं.

14. उक्त विनियमन के विनियम 36 में, उप-विनियम (1) है,—

(ए) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ए) कोई महिला कर्मचारी एक बार में अधिकतम छह महीने और अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम बारह महीने तक मूल वेतन पर मातृत्व अवकाश की पात्र होगी:

हालांकि, जुड़वां बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ महीने होगी:

इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 2024 को और से एक ही प्रसव में दो से अधिक बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व अवकाश की अवधि बारह महीने होगी:

इसके अतिरिक्त, मातृत्व अवकाश को, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाकर लिया जा सकता है.

(बी) खंड (डी) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“(डी) एक महिला कर्मचारी सेवाकाल के दौरान एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए अधिकतम नौ महीने की छुट्टी ले सकती है, जो निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:—

- (i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए ही अवकाश दिया जाएगा;
- (ii) बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए और कर्मचारी को ऐसा अवकाश स्वीकृत कराने के लिए बैंक को गोद लेने का दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए;
- (iii) सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे के मामलों में जैविक मां को भी यह अवकाश उपलब्ध होगा;
- (iv) यह अवकाश सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की कुल पात्रता के भीतर ही लिया जाएगा.

(सी) खंड (ई) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे. अर्थात्:—

“(एफ) 1 अप्रैल, 2024 को और से मातृत्व अवकाश इन विट्रो फर्टिलिटी (आईवीएफ) उपचार के लिए बारह महीने की कुल सीमा के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन लिया जा सकता है.

(जी) 1 अप्रैल, 2024 को और से, शिशु के मृत जन्म या जन्म के अट्टाईस दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में महिला कर्मचारी साठ दिनों तक विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती है.

15. उक्त विनियमन के विनियम 37ए, के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“37ए. (1) 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी, एक अधिकारी कर्मचारी विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए उन अवसरों पर पात्र होगा, जब वह शाखा जहां अधिकारी काम कर रहा है, या वह स्थान जहां वह रह रहा है, कर्फ्यू, दंगे, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आदि से प्रभावित हो.

(2) 1 नवंबर, 2020 से, शारीरिक या आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांक अधिकारी चार दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होंगे.

(3) 1 अप्रैल, 2024 से, अखिल भारतीय अधिकारी संघों या संगठनों के प्रधान पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में पच्चीस दिनों तक का विशेष अवकाश दिया जाएगा.

(4) 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, विभागीय जांच में रक्षा प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत अधिकारी, किसी अधिकारी कर्मचारी की रक्षा संबंधी प्रस्तुति तैयार करने के उद्देश्य से एक दिन का विशेष अवकाश ले सकते हैं:

बशर्ते कि इस प्रकार की विशेष छुट्टी एक वर्ष में अधिकतम दस बार ही ली जा सकेगी.

(5) समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किए जाने पर, किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश और कोई विशेष अवकाश भी दिया जा सकता है.

16. उक्त विनियमन के विनियम 37ए के बाद, निम्नलिखित नियम को शामिल किया जाएगा\_अर्थात्:-

37बी. शोक अवकाश – परिवार के सदस्यों (पति/ पत्नी, बच्चे, माता-पिता और सास-ससुर) के निधन पर किसी अधिकारी कर्मचारी को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिनों का शोक अवकाश दिया जाएगा:

बशर्ते कि बीच में पड़ने वाले अवकाश, शोक अवकाश का हिस्सा होंगे:

इसके अतिरिक्त, उक्त अवकाश मृत्यु के अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए.

इसके अतिरिक्त, विशेषाधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजन से उक्त अवकाश को “सक्रिय सेवा” नहीं माना जाएगा.

17. उक्त विनियमन के विनियम 41 में.

(ए) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) 1 अप्रैल, 2024 को और से, जहां भी किसी अधिकारी को ड्यूटी पर यात्रा करने की आवश्यकता हो, वहां निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्:-

(ए) जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड का अधिकारी किसी भी ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का हकदार होगा, जिसमें राजधानी, शताब्दी, तेजस, वंदे भारत, अमृत भारत आदि जैसी प्रीमियम ट्रेनों भी शामिल हैं (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर).

बशर्ते कि, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारोबारी या सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाती है, तो ऐसा अधिकारी हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) कर सकता है;

(बी) मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी खंड (ए) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा.

बशर्ते कि यदि तय की जाने वाली दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो तो वह हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) कर सकता है:

इसके अतिरिक्त, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारोबारी या सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाए, तो वह कम दूरी के लिए भी हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) कर सकता है;

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यकारी श्रेणी का कोई अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन से एसी प्रथम श्रेणी [जैसा कि खंड (ए) में उल्लेख किया गया है] या हवाई जहाज से (इकोनॉमी श्रेणी में) यात्रा करने का हकदार होगा;

(डी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यकारी श्रेणी का कोई अधिकारी उन स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकता है जो हवाई या रेल मार्ग से जुड़े नहीं हैं, बशर्ते यह दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो.

बशर्ते कि जब दो स्थानों के बीच की अधिकांश दूरी हवाई या रेल मार्ग से तय की जा सकती हो, तो केवल शेष दूरी ही सामान्यतः कार द्वारा तय की जानी चाहिए:

(ई) कारोबार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को अपने वाहन से, टैक्सी से या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

(एफ) किसी भी श्रेणी या वेतनमान का अधिकारी सड़क, हवाई या रेल मार्ग से असंबद्ध स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा;

(जी) एक अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) में किराए का हकदार होगा.

**नोट 1:** ट्रेन के किराए पर लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर आपके हक के अतिरिक्त होगा.

**नोट 2:** प्रचलित गतिशील किराया प्रणाली को देखते हुए, बुकिंग की तारीख पर लगाए गए ट्रेन टिकटों की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

(बी) उप-विनियम (4) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित लागू होगा खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“(ए) विराम भत्ता - 1 अप्रैल, 2024 को और से, सारणी के स्तंभ (2) में निर्धारित ग्रेड या वेतनमानों में कार्यरत अधिकारी, सारणी के स्तंभ (3) में निर्धारित संबंधित दरों पर दैनिक ठहराव भत्ते के हकदार होंगे, अर्थात्:-

## तालिका

क्र. सं.	अधिकारियों के वर्ग या वेतनमान	विराम भत्ता			
		मेट्रो रु.	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर रु.	क्षेत्र I रु.	अन्य स्थानों रु.
(1)	(2)	(3)			
1.	वेतनमान VI और उससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
2.	वेतनमान IV और V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
3.	वेतनमान I, II और III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800:

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किन्तु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

*स्पष्टीकरण-* विराम भत्ते की गणना करने के प्रयोजन हेतु, "प्रतिदिन" का अर्थ चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका पश्चातवर्ती भाग है, जिसकी गणना वायुयान यात्रा की स्थिति में, प्रस्थान के लिए रिपोर्ट के समय से और अन्य स्थितियों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की होगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" से कम से कम आठ घंटे की अवधि अभिप्रेत है।”

18. उक्त विनियमन के विनियम 42 में,

(ए) उप-विनियम (3) के हेतु, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(3) 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी, स्थानांतरण पर एक अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का

बीमा आदि से जुड़े खर्चों के लिए निम्नलिखित सारणी के अनुसार एकमुश्त राशि के आहरण हेतु पात्र होंगे, अर्थात्:

## तालिका

क्र. सं.	वर्ग या वेतनमान	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन (वेतनमान IV एवं ऊपर के अधिकारी)	रु. 50000/-

2.	मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	रु. 40000/-”;
----	--	---------------

(बी) उप-विनियम (4) में, प्रावधान हेतु, निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

“बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, ऐसे मामलों में जहाँ किसी अधिकारी के नए पदस्थापन स्थल पर बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है और जहाँ ऐसा अधिकारी, अपने नियंत्रण से परे कारणों के चलते, कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त व्यय वहन करता है, वहाँ सक्षम प्राधिकारी ऐसे अधिकारी के नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मामले के गुण-दोष के आधार पर, पंद्रह दिनों की अवधि के लिए अथवा उसे आवास उपलब्ध कराए जाने तक (जो भी पहले हो), लॉजिंग एवं बोर्डिंग शुल्क या विराम भत्ता प्रदान किए जाने पर विचार कर सकता है।”

19. उक्त विनियमन के विनियम 44 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“44. अवकाश यात्रा रियायत – (1) चार वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, किसी अधिकारी को प्रत्येक दो वर्षों के ब्लॉक में एक बार अपने स्थायी निवास की यात्रा के लिए अवकाश यात्रा रियायत का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी:

बशर्ते कि वह दो वर्षों के एक ब्लॉक में अपने स्थायी निवास की यात्रा कर सकता है तथा दो वर्षों के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा लघुतम मार्ग से कर सकता है।

(2) 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, वैकल्पिक रूप से, कोई अधिकारी चार वर्षों के ब्लॉक या दो वर्षों के ब्लॉक, जैसा भी मामला हो, के दौरान किसी भी समय एक विकल्प का प्रयोग करते हुए, अपने अवकाश यात्रा रियायत (निवास स्थान की यात्रा को छोड़कर) का समर्पण तथा नकदीकरण कर सकता है, जिस पर वह रेल यात्रा की श्रेणी के लिए पात्र किराये के समकक्ष राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसके लिए कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान-I, मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान-II तथा मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान-III के अधिकारियों के लिए 5,500 किलोमीटर (एकतरफा), और वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान-IV एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 6,500 किलोमीटर (एकतरफा) की दूरी तय की गई है:

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो अपनी अवकाश यात्रा रियायत के नकदीकरण का विकल्प चुनता है, वह उस ब्लॉक के दौरान केवल एक बार अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही दावा प्रस्तुत करेगा, जिसमें इस तरह के नकदीकरण का लाभ उठाया गया है और अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।

(3) जिस मोड एवं श्रेणी के द्वारा एक अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, वह वही होगी जिसके लिए अधिकारी सामान्य रूप से स्थानान्तरण पर यात्रा करने का हकदार है और अन्य नियम एवं शर्तें, जिनके अधीन एक अधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान-I का कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय वायु मार्ग से न्यूनतम किराये वाली इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने का हकदार होगा, ऐसे मामले में प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया या की गई दूरी के लिए रेल से एसी प्रथम श्रेणी के किराए पर लागू किराया होगा, जो भी कम

हो और वही नियम तब भी लागू होंगे जब मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान-II एवं स्केल-III के अधिकारी 500 किलोमीटर से कम दूरी के लिए अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते हैं।

(4) प्रत्येक चार वर्षों में एक बार, जब कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेता है, तब उसे एक बार में अधिकतम 30 दिनों तक का विशेषाधिकार अवकाश समर्पण एवं नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है, अथवा यदि वह दो वर्षों के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर की यात्रा करता है और अन्य ब्लॉक में भारत के किसी अन्य स्थान की यात्रा करता है, तो उसे प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 15 दिनों तक या किसी एक ब्लॉक में अधिकतम 30 दिनों तक विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है और अवकाश नकदीकरण के प्रयोजन हेतु, जिस माह में अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लिया गया हो, उस माह देय सभी परिलब्धियाँ स्वीकार्य होंगी।

बशर्ते कि कोई अधिकारी, अपने विकल्प पर, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दान हेतु एक दिन का अतिरिक्त विशेषाधिकार अवकाश नकद कर सकता है, बशर्ते वह इस आशय का पत्र बैंक को दे तथा संबंधित राशि को कोष में भेजने हेतु बैंक को प्राधिकृत करे।

(5) यदि पति-पत्नी दोनों एक ही बैंक में कार्यरत हों, तो वे अवकाश यात्रा रियायत का लाभ स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

(6) उत्तर-पूर्वी राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए, अवकाश यात्रा रियायत की यात्रा गुवाहाटी से मानी जाएगी तथा उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक की पात्र रेल किराया राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

(7) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह से चेन्नई या कोलकाता तक, लक्षद्वीप से कोच्चि तक, तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर या अन्य ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों की शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के मामलों में, जहाँ सीधे रेल संपर्क उपलब्ध नहीं है, वहाँ कर्मचारियों को उनके निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तक की सामान्य पात्रता के अतिरिक्त, उक्त स्थानों तक का पात्र किराया अवकाश यात्रा रियायत के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

(8) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले किसी अधिकारी के साथ यात्रा करने वाले एस्कॉर्ट को अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्:-

(ए) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की गई हो;

(बी) अधिकारी की शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति ऐसी हो कि यात्रा के लिए एस्कॉर्ट की आवश्यकता हो और किसी भी संदेह की स्थिति में, विभागाध्यक्ष या नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा;

(सी) ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी के पास कोई आश्रित वयस्क पारिवारिक सदस्य उपलब्ध न हो जो उसके साथ यात्रा कर सके;

(डी) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी एवं एस्कॉर्ट, रेल या बस किराये में, यदि कोई रियायत रेलवे या राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती हो, तो उसका लाभ प्राप्त करेंगे; तथा

(ई) कोई अन्य ऐसा व्यक्ति, जो आश्रित के रूप में अवकाश यात्रा रियायत का पात्र हो, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ उस यात्रा में साथ न हो।

(9) यदि किसी अधिकारी ने अवकाश यात्रा रियायत अथवा अवकाश के लिए अग्रिम आवेदन किया हो और टिकट भी बुक कर लिए हो, तथा प्रबंधन द्वारा अवकाश यात्रा रियायत को अस्वीकार या स्थगित कर दिया गया हो, तो टिकट रद्दीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी.

(10) जहाँ किसी अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत अथवा अवकाश के लिए आवेदन किया हो और उसे स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई हो तथा यदि अग्रिम रूप से रेल टिकट बुक करना संभव न हो, तो तत्काल या प्रीमियम तत्काल के अंतर्गत खरीदे गए टिकटों की प्रतिपूर्ति की जाएगी.”

20. उक्त विनियमन की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

**“अनुसूची**

**(विनियमन 23 का उप-विनियमन (2) देखें)**

1 नवंबर, 2022 से प्रभावी, एक अधिकारी नीचे दी गयी तालिका के अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ता पाने का तब तक पात्र होगा, जब तक कि इसे पूर्ण रूप या आंशिक रूप से वापस नहीं ले लिया जाए या संशोधित न कर दिया जाए, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्: -

**तालिका**  
**विशेष क्षेत्र भत्ता**

क्र. सं.	स्थान	भत्ते (रु.)	
		रु. 48,481/- से कम वेतन	रु. 48,481/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम		
	(ए) चिम्पतुईपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक दूर के क्षेत्र.	4100	5300
	(बी) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला.	4100	5300
	(b)		
	(सी) पूरा आइजोल जिला	2700	3400
2.	नागालैंड	4100	5300
3.	अंडमान व नीकोबार द्वीप समूह		
	(ए) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, नीकोबार और नारकोंडम द्वीप	4100	5300
	(a)		
	(बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	4100	5300

4.	सिक्किम	4100	5300
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	4100	5300
6.	असम	1000	1200
7.	मेघालय	1000	1200
8.	त्रिपुरा		
	(ए) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र	4100	5300
	(बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे त्रिपुरा राज्य में	2700	3400
9.	मणिपुर	2700	3400
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(ए) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र	4100	5300
	(बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे अरुणाचल प्रदेश में.	4100	5300
11.	ए. जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश		
	(1) कठुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी	4100	5300
	(2) उधमपुर जिला:		
	(ए) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमाग इलागा, थकरकोटे और नागोटे	4100	5300
	(बी) नीचे (सी) में शामिल के अतिरिक्त मोहरे तहसील में सभी क्षेत्र	4100	5300
	(सी) मोहरे तहसील में कंबन की ओर से गोयल तक के क्षेत्र और कियासी की ओर से अरनस तक के क्षेत्र	4100	5300
	(3) डोडा जिला: पैडर का इलाका और कश्मीर तहसील में नियाबत नौगावं	4100	5300
	(4) बारामुल्ला जिला:		
	(ए) संपूर्ण गुरेज़- निराबात, तंगदार उप-मंडल और केरन इलाका	4100	5300
	(बी) मचेल	4100	5300
	(5) पूँछ और राजौरी जिला: पूँछ और राजौरी तथा सुंदरबनी और दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पूँछ और राजौरी जिले के क्षेत्र	2700	3400
	(6) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (5) में शामिल नहीं हैं, किन्तु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी. की दूरी के भीतर हैं या ऐसे स्थान हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ते के लिए पात्र के रूप में घोषित किया जा सकता है.	2700	3400
11.	बी. लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश लेह जिला: नोयमा एवं नोबरे जनस्कर जिला में अन्य सभी स्थान	4100	5300
12.	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चंबा जिला		
	(ए) पांगी तहसील, भरमौर तहसील में निम्नलिखित पंचायतें और गांव: पंचायत: बदगांव , बाजोल, देओल कुगती, नयागाम और टुंडा, गांव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा के कनारसी	4100	5300
	(बी) भरमौर तहसील, उपरोक्त (ए) में शामिल लिए गए पंचायतों और गांवों को छोड़कर.	4100	5300
	(सी) भारतीय तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाऊन (बनीखेत सहित)	2700	3400
	(2) किन्नौर जिला		
	(ए) असरंग , चितकुल और हांगोकुनो या चारंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें ऊपर निर्दिष्ट पंचायत	4100	5300

	क्षेत्रों को छोड़कर छोटा खम्बा, नाथपा और रूपी, पूह उप-मंडल, की ग्राम पंचायतें शामिल हैं.		
	(बी) उपरोक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण जिला.	4100	5300
	(3) कुल्लू जिला:		
	(ए) निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायत शामिल है.	4100	5300
	(बी) बाहरी- सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बरो के गांवों को छोड़कर) और, बाहरी सराज क्षेत्र और पंडराबिस के परगना को छोड़कर, लेकिन निरमंड तहसील के जगत- खाना और बरो गांव सहित संपूर्ण जिला)	2700	3400
	(4) लाहौल और स्पीति जिला: लाहौल एवं स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	4100	5300
	(5) शिमला जिला		
	(ए) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें कूट, लवाना-सदाना, सरपारा और चंडी-ब्रांडा के पंचायत शामिल हैं.	4100	5300
	(बी) डोरा कवर तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापठ तहसील और मुनीश, सरहन परगना का घोरीचाइबीस.	4100	5300
	(सी) (i) चौपाल तहसील (ii) (ए) परगना सरहन के घोरीस, पंजगाँव, पट्सनऊ, नौबीस और तीनकोटि, (बी) तकलेश क्षेत्र का देओती ग्राम पंचायत, (सी) परगना बरबीस, (डी) रामपुर तहसील का कस्बा रामपुर और परगना रामपुर का घोरी नोग, (डी) शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जतोग, कसूम्टी, मशोबरा, तारादेवी और तुतू).	2700	3400
	(6) कांगड़ा जिला:		
	(ए) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र	4100	5300
	(I) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और निम्नलिखित कार्यालय जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित हैं लेकिन धर्मशाला शहर में शामिल हैं: (ए) महिला आईटीआई, दारी, (बी) यांत्रिक कार्यशाला, रामनगर, (सी) बाल कल्याण और नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, सकोह, (डी) लोअर सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, (ई) कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, डुगियार, (एफ) एचआरटीसी कार्यशाला, सधेर, (जी) जोनल मलेरिया कार्यालय, दारी, (एच) वन निगम कार्यालय, शामनगर, (आई) चाय फैक्ट्री, दारी, (जे) आई.पी.एच. उप-मंडल, दारी (के) बंदोबस्ती कार्यालय, शामनगर, (एल) बिनवा परियोजना, शामनगर,  (II) पालमपुर में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (एचपीकेवीवी) परिसर सहित पालमपुर शहर और निम्नलिखित कार्यालय जो इसके नगर निगम सीमा के बाहर स्थित हैं लेकिन पालमपुर शहर में शामिल हैं -	2700	3400

	(ए) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय परिसर, (बी) मवेशी विकास कार्यालय / जर्सी फार्म, बनूरी, (सी) रेशम उत्पादन कार्यालय / इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंदला, (डी) विद्युत उप-डिवीज़न, लोहना (ई) डीपीओ निगम, बुंदला, (एफ) विद्युत एचईएसईई डिवीज़न, घुग्गर		
	(7) मंडी जिला:		
	जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, <b>थुनाग तहसील में पंचायत:</b> बागडा, चतरी, छोटधार, गरागुशैन, गट्टू, गरियास, जंझेली, जरयार, जोहार कलहाणी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, सोमचान, थचधार, ताची, थाना. <b>धर्मपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायत:</b> बिंगा, कमला, सकलाना, तन्यर और तरखोला करसोग तहसील के पंचायत – बलीधार, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहुदी, माँज, पेखी, सैज, सराहन और टेवन, सुंदरनगर तहसील के पंचायत - बोही, बटवारा, धन्यारा, पौरा -कोठी, सेरी और शोजा	2700	3400
	(8) सिरमौर जिला: (ए) निम्नलिखित पंचायत (i) बानी, बाखली (पछाद तहसील); (ii) भरोग भनेरी ( पावंटा तहसील); (iii) बिरला (नाहन तहसील); (iv) डिब्बर (पछाद तहसील); और (v) थाना कसोगा (नाहन तहसील) (बी) थांसगिरि भूभाग	2700	3400
	(9) सोलन ज़िला: मंगल पंचायत.	2700	3400
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त (1) से (9) में सम्मिलित नहीं हैं.	1000	1200
13.	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4100	5300
14.	पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला  सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा से दक्षिण), अर्थात्, भानातुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजना खली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नालगढ़ा, रायदिघी, भांची, पाथर प्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, शिकारपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुमारी, कुलटोला, घुशिघाटा (कुल्टी)	1000	1200.”.

सुरेश चंद्र तेली, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./112/2026-27]

**नोट:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात भारत के राजपत्र, भाग-III, अनुभाग-4 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से इनमें संशोधन किया गया है, अर्थात्:-

क्रम सं.	राजपत्र अधिसूचना सं.	आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	ओएसआर/1	14.11.1987
2.	ओएसआर/2	04.06.1988
3.	ओएसआर/3	04.06.1988
4.	ओएसआर/4	30.12.1989
5.	ओएसआर/5	27.10.1990
6.	ओएसआर/6	11.01.1992
7.	ओएसआर/7	12.12.1992
8.	ओएसआर/8	27.02.1993
9.	ओएसआर/9	25.09.1993
10.	ओएसआर/10	10.09.1994
11.	ओएसआर/11	07.01.1995
12.	ओएसआर/12	07.09.1996
13.	ओएसआर/13	21.12.1996
14.	ओएसआर/14	21.12.1996
15.	ओएसआर/15	21.12.1996
16.	ओएसआर/15	06.02.1996
17.	ओएसआर/16	03.06.2000
18.	ओएसआर/16	30.12.2000
19.	ओएसआर/17	09.12.2000
20.	ओएसआर/18	29.10.2002
21.	ओएसआर/19	18.06.2003
22.	ओएसआर/20	27.01.2006
23.	ओएसआर/21	10.03.2007
24.	ओएसआर/22	25.09.2017
25.	ओएसआर/23	31.03.2020
26.	ओएसआर/24	27.11.2024

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

ये विनियमन जो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए गए हैं, वे भारतीय बैंक संघ द्वारा, सदस्य बैंकों की ओर से इस संबंध में संबंधित बैंकों से प्राप्त विशिष्ट अधिदेश के आधार पर तथा बैंकों के शीर्ष-स्तरीय अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के सहमत शर्तों एवं नियमों के अनुरूप हैं। अतः ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**UNION BANK OF INDIA  
NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th May, 2026

**F. No. CO:ERD:PD:225:2026.**— In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Union Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13<sup>th</sup> March, 2024, on and from the 1<sup>st</sup> November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Union Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Union Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Union Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

“(f) ‘family’, in relation to an Officer employee for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, shall mean—

- (i) the Officer employee's spouse;
- (ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);
- (iii) wholly dependent physically and mentally challenged brothers or sisters with forty per cent. or more disability;
- (iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;
- (v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters; and
- (vi) parents wholly dependent on the employee:

Provided that in the case of physically or mentally challenged children irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage subject to fulfilling the income criteria for dependent.

*Explanation 1.*— The term wholly dependent family member shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs.18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs.18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs. 18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the Officer employee.

*Explanation 2.*— For the purposes of medical expenses reimbursement scheme, and Leave Fare Concession, for all Officer employees, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered. The Officer employee will have the choice to substitute either of the dependents or both once in a calendar year.

*Explanation 3.*—This definition shall be effective from the 1<sup>st</sup> April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme or policy, the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1<sup>st</sup> November, 2024.”.

3. In regulation 4 of the said regulations,—

- (a) the *Explanation* to sub-regulation (7) shall be omitted;

(b) for sub-regulations (9) and (10), the following shall be substituted, namely:—

“(9) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VIII = Rs. 253000 – 9000/4 – 289000

Scale VII = Rs. 156500 – 4340/4 – 173860

Scale VI = Rs. 140500 – 4000/4 – 156500

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs. 120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 – 135020

Scale IV = Rs. 102300 – 2980/4 – 114220 – 3360/2 – 120940

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs. 85920 – 2680/5 – 99320 – 2980/2 – 105280

Scale II = Rs. 64820 – 2340/1 – 67160 – 2680/10 – 93960

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs. 48480 – 2000/7 – 62480 – 2340/2 – 67160 – 2680/7 – 85920.

*Explanation.*— Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31<sup>st</sup> October, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on the 1<sup>st</sup> November, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(10) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(11) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III – 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V – 10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII – 11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

(12) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III – 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale IV – V – 19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VI - VIII – 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon:

Provided that an Officer in Scale-VIII will be eligible for special allowance on and from the 31<sup>st</sup> March, 2020.

(13) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale II – III – 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale IV – V – 30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VI – VII – 31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VIII – 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

**Note:** The special allowance referred to in sub-regulations (11), (12) and (13) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (9) of regulation 4, on and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: –

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (9) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below, subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for seven stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 2680/- each and the next five shall be of Rs 2980/-each:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later;

- (d) officers in Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments of Rs 2980/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments for every two years of completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs 2980/- and the next four stagnation increments shall be of Rs 3360/- each:

Provided that the officer shall be eligible for seventh stagnation increment two years after release of sixth stagnation increment or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of sixth stagnation increment or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs 3360/- and the next four stagnation increments shall be of Rs 3680/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of second stagnation increment or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of second stagnation increment or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of second stagnation increment or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later;

- (g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments of Rs 4000/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later;

- (h) officers in Top Management Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs 4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs 4340/-:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs 4000/- two years after reaching the maximum of scale or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs 4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs 4340/- six years after reaching the maximum of scale or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later;

- (i) officers in Top Management Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments of Rs 4340/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later:

Provided also that the Officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later.

Note: The increments as mentioned in clauses (a) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

*Explanation.*— Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

- (b) in sub-regulation (2),—

- (i) before the *Explanation*, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, officers completing Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ examination (JAIIB) or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-I):

Provided further that officers who were in the services of the Bank as on the 1<sup>st</sup> November, 2022 and have already completed CAIIB-II shall be eligible for second additional increment from the 1<sup>st</sup> November, 2022 or date of passing CAIIB-II, whichever is later:

Provided also that in case where an officer, as on the 8<sup>th</sup> March, 2024, has already acquired or acquires JAIIB or CAIIB I or CAIIB (CAIIB II) after reaching top or maximum of the scale of Pay (in case of JAIIB or CAIIB) or after reaching the stage which is one stage less than maximum of scale of pay (in case of JAIIB or CAIIB I or CAIIB II), and has not earned increments, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of Pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years, as the case may be.”;

- (ii) in the *Explanation*, after clause (h) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(i) on and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the following Table, namely:—

**Table**

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(a) Rs. 1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale; (b) Rs.3425/- per month two years after reaching maximum of the Scale; and (c) Rs.5480/- per month three years after reaching maximum of the Scale:

Provided that an officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2022, no Professional Qualification allowance shall be payable to an officer employee working in Scale VIII.”;

(iii) in the Note, after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely: –

“(vi) officers who were in the services of the Bank as on the 1<sup>st</sup> November, 2022, and have already completed JAIIB or CAIIB or CAIIB II and drawing Professional Qualification Pay -II shall be eligible for Professional Qualification Pay -III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or from the 1<sup>st</sup> November, 2022, whichever is later.

(vii) officers who have completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before the 1<sup>st</sup> November, 2022 and has not received the 1<sup>st</sup> stagnation increment on or before the 1<sup>st</sup> November, 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, and release of subsequent installment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I under this clause.”;

(c) in sub-regulation (3),–

(i) in clause (g), after the Table, Notes (i) to (vi), shall be omitted;

(ii) after clause (h), the following shall be inserted, namely:–

“(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

Table

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on the 1 <sup>st</sup> November, 2022 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669.

**Note:**

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Table in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) (h) and (i) of this sub-regulation shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the Table under clause (i) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2),(3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned;
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1<sup>st</sup> November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.
- (iv) On and from the 1<sup>st</sup> November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in clause (c) of the *Explanation* to sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:
- Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1<sup>st</sup> November, 2000.
- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation, one year after reaching the maximum of the scale.”.

5. In regulation 21 of the said regulations,—

- (a) in sub-regulation (6), in the *Explanation*, for clause 6, the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of the *Explanation* to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.”;

(b) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(8) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2022,—

- (a) Dearness Allowance shall be payable at 1 per cent. of pay per percentage point of Index;
- (b) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base 2016=100. 0.01 per cent. change in Dearness Allowance on pay for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points;
- (c) the change in the Dearness Allowance rate shall be released on a quarterly basis on 1<sup>st</sup> May, 1<sup>st</sup> August, 1<sup>st</sup> November and 1<sup>st</sup> February based on the following, namely:—

<b>Dearness Allowance release date</b>	<b>Quarterly average of Consumer Price Index points of the months</b>	<b>Applicable for the month</b>
1 <sup>st</sup> May	January, February and March	May, June and July
1 <sup>st</sup> August	April, May and June	August, September and October
1 <sup>st</sup> November	July, August and September	November, December and January
1 <sup>st</sup> February	October, November and December	February, March and April;

- (d) there shall be no ceiling on Dearness Allowance;
- (e) while working out quarterly average, only first two decimals shall be considered.”.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2022,—

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:—

**Table**

<b>Sl. No.</b>	<b>Place of work</b>	<b>House Rent Allowance</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	10.0% of Pay
2.	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	9.0% of Pay
3.	Other places	8.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (3) of the above Table.

**Note:** The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto."

7. In regulation 23 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"23. (1) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, if an officer is serving in a place specified in column (2) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate specified in column (3) thereof against that place shall be payable:

**Table**

<b>Sl. No.</b>	<b>Places</b>	<b>Rate</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Places in Area 1 and above and in the State of the Goa	Rs. 2300/- per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1900/- per month.

(2) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (1) of the Schedule, Hill and Fuel Allowance as provided under sub-regulation (10) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances, and not both:

Provided further that of such higher of the two allowances is less than the aggregate of Special Allowance and Hill and Fuel Allowance drawn by the officer on the 31<sup>st</sup> December, 1989, then such difference shall be protected as Personal Allowance till such time the officer remains at that place.";

(3) On and from the 1st November, 2017, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.600/- per month or Rs.525/- per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.

(4) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.2500/-per month per child with a maximum upto two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year:

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month:

Provided further that where an Officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major A class cities where the distance of such deputation is twenty kilometre and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as provided in sub-regulation (4) of regulation 41.

(6) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 15 per cent. of his Basic Pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

(7) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.

(8) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs. 300 per month.

(9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday a Diem Allowance at the rate to which he is entitled is payable.

- (10) On and from the 1<sup>st</sup> November 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the Table below, namely:-

<b>Table</b>		
<b>Sl. No.</b>	<b>Place</b>	<b>Rate</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month
2.	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month
3.	Place with an altitude of 3000 metres and above	5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month.

- (11) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs 850/-per month along with Dearness Allowance thereon.

Note: Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

- (12) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, an officer shall be eligible for a fixed Location Allowance of Rs.1200/- per month, who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance, which shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, that is, pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

- (13) (a) From the financial year 2023-24, Performance Linked Incentive shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters, namely: -

- (i) Current Account Saving Account;
- (ii) Non-Performing Assets;
- (iii) Special Mention Accounts;
- (iv) Non – interest income;
- (v) Total Business;
- (vi) Profitability;
- (vii) Return on Assets or Return on Equity;
- (viii) Government Schemes.

- (b) The Performance Linked Incentive amount shall be payable in 0-15 (maximum) number of days of pay (Basic + Dearness Allowance) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a).”.

8. In regulation 24 of the said regulations, –

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of own certificate of the officer of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely:—

<b>Table</b>		
<b>Sl. No.</b>	<b>Grade</b>	<b>Maximum limit of reimbursement</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.13000/- per annum or the amount incurred, whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.15400/- per annum or the amount incurred, whichever is less

Note 1 : An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Note 2 : For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2022 and December, 2022.”;

(b) after sub-regulation (3), following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) All officer employees shall also be eligible for reimbursement of Rs. 500/- per year towards eye check-up.”.

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), on and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075 per cent. of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 31 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where the Sanctioning Authority refuses or postpones the leave of the officer, it shall record the reasons for the same in writing.”.

11. In regulation 32 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(3) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, an officer employee shall be eligible to avail two days casual leave for half- a day on four occasions in a year, out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon:

Provided that casual leave under this category shall be availed after applying twenty-four hours in advance:

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.”.

12. In regulation 33 of the said regulations, –

(a) for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(4) On and from the 1<sup>st</sup> June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred fifty five days:

Provided further that an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty-five years of age and above shall be eligible to encash Privilege Leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement.

(5) An officer desiring to avail of Privilege Leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention to avail such leave except for the purpose of Leave Fare concession:

Provided that on and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, no such advance notice of ten days shall be required for availing Privilege Leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.”;

(b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(7) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, for the purposes of calculating Privilege Leave, all types of leave availed except casual leave and mandatory leave shall be excluded.”.

13. In regulation 34 of the said regulations,—

(a) in sub-regulation (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave (including additional sick leave mentioned in regulation 35) shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.”;

(b) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(6) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of eight years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate.

(8) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, officer employees may avail sick leave for the sickness of their special child of fifteen years and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate.

(9) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, officer employees of the age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalisation of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.”.

14. In regulation 36 of the said regulations, is sub-regulation (1),—

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) A female employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that on and from the 1<sup>st</sup> April, 2024 in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months:

Provided also that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave.”;

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted:—

“(d) A female employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;

(iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.”;

(c) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(f) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, maternity leave may be availed for in vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months.

(g) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty-eight days of birth.”.

15. For regulation 37A of the said regulation, the following regulation shall be substituted, namely:—

“37A. (1) With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2020, an officer employee shall be eligible for Special Casual Leave on occasions when the branch where the officer is working, or the place where he is residing, is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods and the like.

(2) With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) With effect from the 1<sup>st</sup> April, 2024, the Principal Officer bearers of All India Officers’ Unions or Associations shall be granted Special Leave upto twenty-five days in a calendar year.

(4) With effect from the 1<sup>st</sup> April, 2024, officers who are defense representatives in departmental enquiry, may avail one day special leave for the purpose of preparing the defense submission of an officer employee:

Provided that such special leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

(5) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.”.

16. After regulation 37A of the said regulation, the following regulation shall be inserted, namely:—

“37B. Bereavement leave.— An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays will form part of the bereavement leave:

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of fifteen days of the demise.

Provided also that the said leave shall not be considered as “Active service” for the purpose of calculation of privilege leave.”.

17. In regulation 41 of the said regulations. —

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

- (a) an officer in Junior Management Grade shall be entitled to travel by AC 1<sup>st</sup> class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

- (b) An officer in Middle Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kilometers:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance, if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

- (c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any train including premium trains [as mentioned in clause (a)] or by air (economy class);

- (d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car:

- (e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;

- (f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail;

- (g) an Officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

**Note 1:** Goods and Services Tax Charges levied on train fare shall be over and above the entitlement.

**Note 2:** In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed.”;

- (b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) Halting Allowance - On and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales set out in column (2) of the Table shall be entitled to *per diem* Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (3) thereof, namely:—

<b>Table</b>					
Sl. No.	Grades or Scales of officers	Halting Allowance			
		Metro Rs.	Major 'A' Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
(1)	(2)	(3)			
1.	Officers in Scale VI and above	4050	2925	2475	2150
2.	Officers in Scale IV and V	3375	2925	2475	2150
3.	Officers in Scale I, II and III	2925	2475	2150	1800:

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

*Explanation.*— For the purpose of computing Halting allowance, *per diem* shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “*per diem*” shall mean a period of not less than eight hours.”.

18. In regulation 42 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) On and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:—

<b>Table</b>		
Sl. No.	Grade or Scale	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Senior Management and Top Executive (officers in Scale IV and above)	Rs.50000/-
2.	Junior Management and Middle Management (officers upto Scale III)	Rs.40000/-”;

(b) in sub-regulation (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that on and from the 1<sup>st</sup> April, 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either lodging and boarding charges, or Halting Allowance for a period of fifteen days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.”.

19. For regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“44. Leave travel Concession.— (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) With effect from the 1<sup>st</sup> April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometers (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III and 6,500 kilometers (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1<sup>st</sup> April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I, while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1<sup>st</sup> Class fare by train for the distance travelled, whichever is less and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession, where the distance is less than 500 kilometers.

(4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding thirty days at a time or he may, while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the leave travel concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer, at his option, shall be permitted to encash one day additional privilege leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

(5) Leave Travel concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.

(6) For employees working in North-east States, Leave Travel concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.

(7) The eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.

(8) Leave Travel concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an officer with benchmark disabilities on the journey subject to the following conditions, namely:—

- (a) prior approval of the competent authority is obtained on each occasion;
- (b) the nature of physical disability of the officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;
- (c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him or her;
- (d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the Rail or Bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and
- (e) any other person who is entitled to Leave Travel concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.

(9) Where an officer has applied for Leave Travel concession or Leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Travel concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank.

(10) Where an officer has applied for Leave Travel concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium tatkal shall be reimbursed.”.

20. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:—

**“SCHEDULE**

**[See sub-regulation (2) of regulation 23]**

On and from the 1<sup>st</sup> November, 2022, an officer shall be eligible for Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified, either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:—

**Table**  
**Special Area Allowance**

Sl. No.	Place	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.48,481/-	Pay above Rs. 48,481/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chimgtuipui district and areas beyond 25 kilometers from Lunglei town in Lunglei district.	4100	5300
	(c) Entire Lunglei district excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town	4100	5300
	(d) Entire Aizawl district	2700	3400
2.	Nagaland	4100	5300
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(b) North Andaman, middle Andamans, little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4100	5300
	(c) South Andaman (including Port Blair)	4100	5300
4.	Sikkim	4100	5300
5.	Lakshadweep Islands	4100	5300
6.	Assam	1000	1200
7.	Meghalaya	1000	1200
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	4100	5300
	(b) Throughout Tripura except difficult areas	2700	3400
9.	Manipur	2700	3400
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4100	5300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas	4100	5300
11.	A. Union territory of Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4100	5300
	(2) Udhampur District:		
	(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote	4100	5300
	(b) All areas in Mahore tehsil other than those included in (c) below	4100	5300
	(c) Areas upto Goel from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre	4100	5300
	(3) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil	4100	5300
	(4) Baramulla District:		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar sub-division and Keran Illaqua	4100	5300
	(b) Matchill	4100	5300

	(5) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two districts	2700	3400
	(6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of eight kilometers from the Line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.	2700	3400
11.	B. Union territory of Ladakh: Leh District: Noyama and Nobre Zanskar All other places in the District	4100	5300
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Following Panchayats and villages in Bharmour Tehsil: Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4100	5300
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and villages included in (a) above	4100	5300
	(c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie town (including Banikhet proper)	2700	3400
	(2) Kinnaur District		
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats, 15/20 area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat areas specified above	4100	5300
	(b) Entire district other than areas included in (a) above	4100	5300
	(3) Kullu District		
	(a) 15/20 area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4100	5300
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire district excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand)	2700	3400
	(4) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	4100	5300
	(5) Shimla District		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda	4100	5300

(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan	4100	5300
(c) (i) Chopal Tehsil (ii) (A)Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, (B) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, (C) Pargana Barabis, (D) Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, (d) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu)	2700	3400
(6) Kangra District:		
(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	4100	5300
(I) Dharamshala town of Kangra district and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala town: (a) Women's ITI, Dari, (b) Mechanical Workshop, Ramnagar, (c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, (d) CRSF Office at lower Sakoh, (e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, (f) HRTC Workshop, Sadher, (g) Zonal Malaria Office, Dari, (h) Forest Corporation Office, Shamnagar, (i) Tea Factory, Dari, (j) I.P.H. Sub- Division, Dari (k) Settlement Office, Shamnagar, (l) Binwa Project, Shamnagar,  (II) Palampur town, including Himachal Pradesh Krishi Vishwa Vidyalaya (HPKV) Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town –  (a) H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, (b) Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, (c) Sericulture office/Indo- German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, (d) Electrical Sub-Division, Lohna, (e) D.P.O. Corporation, Bundla, (f) Electrical HPSE Division, Ghuggar	2700	3400

	(7) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil: Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Following Panchayats of Dharampur Block: Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja	2700	3400
	(8) Sirmaur District: (a) Following Panchayats of (i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil); (ii) Bharog Bheneri (Paonta Tehsil); (iii) Birla (Nahan Tehsil); (iv) Dibber (Pachhad Tehsil); and (v) Thana Kasoga (Nahan Tehsil) (b) Thansgiri Tract	2700	3400
	(9) Solan District: Mangal Panchayat.	2700	3400
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above	1000	1200
13.	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat districts	4100	5300
14.	West Bengal: South 24 Parganas District Sunderban areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata (Kulti)	1000	1200.7.

SURESH CHANDRA TELI, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./112/2026-27]

**Note:** The Union Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 were published in the Gazette of India and subsequently amended *vide* following notifications, published in the Gazette of India, Part III, section 4, namely:-

Sl. No.	Gazette notification Number	Date of publication in the Official Gazette
1.	OSR/1	14.11.1987
2.	OSR/2	04.06.1988
3.	OSR/3	04.06.1988
4.	OSR/4	30.12.1989
5.	OSR/5	27.10.1990

6.	OSR/6	11.01.1992
7.	OSR/7	12.12.1992
8.	OSR/8	27.02.1993
9.	OSR/9	25.09.1993
10.	OSR/10	10.09.1994
11.	OSR/11	07.01.1995
12.	OSR/12	07.09.1996
13.	OSR/13	21.12.1996
14.	OSR/14	21.12.1996
15.	OSR/15	21.12.1996
16.	OSR/15	06.02.1996
17.	OSR/16	03.06.2000
18.	OSR/16	30.12.2000
19.	OSR/17	09.12.2000
20.	OSR/18	29.10.2002
21.	OSR/19	18.06.2003
22.	OSR/20	27.01.2006
23.	OSR/21	10.03.2007
24.	OSR/22	25.09.2017
25.	OSR/23	31.03.2020
26.	OSR/24	27.11.2024

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.